



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2015/पौष 18, 1936

No. 07]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2015/PAUSHA 18, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2015

विषय:—संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) और चीन जन गण में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित मिथायल एसिटोएसिटेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच की शुरुआत – के संबंध में।

सं. 14/7/2014-डी जी ए डी.—यतः, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और चीन जन. गण. (जिन्हें एतदपश्चात् सम्बद्ध देश कहा गया है) में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित मिथायल एसिटोएसिटेट (जिसे एतदपश्चात् सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच प्रारम्भ करने के लिए दायर की है और सम्बद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है।

2. और यतः, प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि सम्बद्ध देशों में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन. घरेलू उद्योग को क्षति. तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक सम्बंध के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं, इसलिए प्राधिकारी, एतद्वारा सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के सम्बंध में एक पाटनरोधी जांच पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुरूप कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए आरम्भ करते हैं, जो यदि उद्ग्रहित की गई तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग एवं आधार

3. यह याचिका मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर की गयी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने सम्बद्ध वस्तु का सम्बद्ध देशों से न तो आयात किया है और न ही उनका सम्बद्ध देशों में इस उत्पाद के किसी निर्यातक या आयातक के साथ कोई सम्बंध है; यह कि वे भारत में सम्बद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं और इस विचाराधीन उत्पाद का भारत में कोई अन्य उत्पादक नहीं है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक इण्डस्ट्रीज

लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात् घरेलू उद्योग या आवेदक कहा गया है) नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह आवेदन पत्र प्रमुख नियमावली के नियम 5(3) में उल्लिखित आधार के मानदण्ड को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मिथायल एसिटोएसिटेट है। वर्तमान जांच में मिथायल एसिटोएसिटेट (जिसे एमएए/एमएई/एएएमई के नाम से भी जाना जाता है) डाइकेटीन आधारित ईस्टर या एसिटोएसिटेट है। ईस्टर्स अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके अल्कोहलों तथा अम्लों के साथ-साथ ताप परिमोचित करता है। सुदृढ़ आक्सिडाइजिंग अम्ल प्रबल प्रतिक्रिया कर सकते हैं जो प्रतिक्रिया उत्पादों को प्रदीप्त करने के लिए पर्याप्ततः अग्नि उत्पादक होते हैं। ईस्टर्स कास्टिक घोलों के साथ अन्योन्यक्रिया करके भी ताप सृजित करते हैं। ईस्टर्स का अल्कलाय धातुओं और हाइड्राइड के साथ मिश्रण करके भी ज्वलनशील हाइड्रोजन का सृजन किया जा सकता है।

5. मिथायल एसिटोएसिटेट का प्रयोग फार्मास्युटिकल उद्योग, कृषि रसायन उद्योग, पालिमर उद्योग में तथा अन्य उद्योगों में रिएक्टेन्ट के रूप में प्रयोग होता है। एम एए का प्रयोग फ्लेवरिंग एजेंट और कलरैन्ट्स के रूप में भी किया जाता है।

6. मिथायल एसिटोएसिटेट को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 में उपशीर्षक संख्या 29183040 के अंतर्गत 'मिथायल एसिटोएसिटेट' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस विचाराधीन उत्पाद का सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अंतर्गत समर्पित सीमाशुल्क वर्गीकरण है। आयात आंकड़ों का आकलन करने पर यह पाया गया कि सम्बद्ध वस्तु का आयात अन्य विभिन्न वर्गीकरणों के अंतर्गत भी किया जाता है। इसलिए, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में प्रस्तावित जांच के दायरे के अंतर्गत बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

7. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह सम्बद्ध वस्तु, जिसका भारत में कथित रूप से पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। उपभोक्तागण उनका प्रयोग अन्तर्निमेष रूप से कर सकते हैं और कर रहे हैं। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ यह विचार किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और सम्बद्ध देशों से आयातित उत्पाद अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों जैसे भैतिक एवं तकनीकी विशिष्टताओं विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय हैं। दोनों ही वाणिज्यिक रूप से और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा सम्बद्ध देशों से आयात की जा रही सम्बद्ध वस्तु को "समान वस्तु" के रूप में मानते हैं।

सम्बद्ध देश

8. वर्तमान जांच में अंतर्ग्रस्त देश संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) और चीन जन गण है।

सामान्य मूल्य

9. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि चीन जन गण को गैर-बाजार-अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

10. सम्बद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग में प्रचलित प्रमुख कच्चे माल की दरों को अपनाकर विनिर्मित किया गया है। यूएसए के लिए यूएसए में प्रचलित उपयोगिता कीमतों को अपनाया गया है। चीन के लिए घरेलू उद्योग की उपयोगिता कीमतों को अपनाया गया है। विनिर्मित सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की अन्य लागतों पर विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

11. याचिकाकर्ता ने सम्बद्ध देशों के बारे में निर्यात कीमत का दावा गौण स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया है और उसी को इस जाँच शुरुआत के लिए अपनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन, पैकिंग, अन्तरदेशीय भाड़ा, उतराई/चढ़ाई और पत्तन प्रभार के आधार पर कीमत समायोजन की अनुमति दी है।

12. याचिकाकर्ता ने इस तथ्य के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान कराए हैं कि सम्बद्ध देशों में सम्बद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से पर्याप्त रूप से उच्चतर है जिससे प्रथमदृष्टया यह संकेत मिलता है कि सम्बद्ध देशों में उदभूत अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है जो पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराती है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

13. याचिकाकर्ता ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो पाटित आयातों की सम्बर्धित मात्रा, कीमत अधोरदन, कीमत निग्रहण और लाभप्रदायकता, लगाई गई पूंजी पर आवक में गिरावट से स्पष्ट है। सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों के द्वारा कारित क्षति को याचिकाकर्ता द्वारा सहन किए जाने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

जांच की अवधि

14. जांच की अवधि (पी ओ आई) 01.04.2013 से 31.06.2014 है। तथापि क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12, 2012-13 के आंकड़ों तथा जांच की प्रस्तावित अवधि के आंकड़ों पर भी विचार किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों तथा उनकी सरकार को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से निम्नलिखित समय-सीमा के अंदर सभी संगत जानकारी दर्ज करने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी निम्नलिखित समय-सीमा के अंदर निर्धारित स्वरूप और ढंग से जांच से संगत प्रस्तुतीकरण कर सकता है। सूचना/प्रस्तुतीकरण निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जा सकता है:—

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे उल्लिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग से जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले किसी अन्य पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा।

समय सीमा

17. वर्तमान जांच से संबंधित किसी सूचना को लिखित रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे कि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस पत्र के संप्रेषण की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अधिक समय में पहुंच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

18. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के अंदर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

19. प्रश्नावली प्रत्युत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष किसी प्रस्तुति (इससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों से इसे दो पृथक सेटों में यदि इसके किसी भाग पर "गोपनीयता" का दावा किया जाता है, फाइल किया जाना अपेक्षित है:—

- (क) एक सेट गोपनीय रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया हो, और
- (ख) दूसरा सेट अगोपनीय के रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया हो।

20. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" की प्रस्तुति को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" रूप में स्पष्टतः चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्हांकन के बिना की गई प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय रूप में समझी जाएगी और प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि ऐसे प्रस्तुति का निरीक्षण करने के लिए वह अन्य इच्छुक पक्षकारों को अनुमति प्रदान करें। दोनों संस्करणों की साफ्ट कापी भी प्रत्येक के पांच (5) सेटों में हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

21. गोपनीय संस्करण में ऐसी सभी सूचनाएं समाविष्ट होंगी जो प्रकृति में गोपनीय हो और/अथवा कोई अन्य सूचना जिसके बारे में ऐसी सूचना की आपूर्ति करने वाला गोपनीयता के रूप में दावा करता हो। सूचना जिसकी प्रकृति में गोपनीयता के रूप में दावा किया जाता है अथवा सूचना जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, के लिए, सूचना आपूर्तिकर्ता से प्राप्त सूचना कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है, के साथ एक उचित कारणों का विवरण दिया जाना अपेक्षित है।

22. अगोपनीय संस्करण सूचना अनुक्रमित अथवा रिक्त किए गए (यदि अनुक्रमणिका संभव न हो) और जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सार रूप में की गई गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार इतने विस्तृत रूप में हो कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की पर्याप्त समझ प्राप्त हो सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसका सार प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

23. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात् गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

24. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में सद्कारण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

25. प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लिए जाने पर प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशेष रूप में प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. प्राटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी सूचना की पहुँच तक मनाही करता है और युक्तिसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties)

Initiation Notification

New Delhi, the 7th January, 2015

Subject: : Initiation of anti-dumping investigation in respect of imports of Methyl Acetoacetate originating in or exported from United States of America (USA), and China PR—reg.

No.14/7/2014-DGAD.— Whereas M/s Laxmi Organic Industries Ltd has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti-dumping duty investigation concerning imports of Methyl Acetoacetate (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from United States of America (USA) and China PR (hereinafter also referred to as the subject countries) and requested the Authority for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

2. And whereas, the Authority finds that the petition filed by M/s Laxmi Organic Industries Ltd. contains sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry; and the causal link between the alleged dumping and injury, to justify initiation of anti-dumping investigation, and the Authority hereby initiates anti-dumping investigation into the alleged dumping of the subject goods from the subject countries, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry and Standing

3. The petition has been filed by M/s Laxmi Organic Industries Ltd. The petitioner has claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or importer of the product in the subject countries; that they are the only producer of the subject goods in India and there is no other producer of the product under consideration in India. As per the evidence available on record, the Authority notes that the production of the petitioner accounts for the total domestic production of the like article. The Authority, therefore, determines that M/s Laxmi Organic Industries Ltd. (hereinafter referred to as the domestic industry or the petitioner) constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

4. The product under consideration in the present petition is Methyl Acetoacetate. Methyl Acetoacetate (also known as MAA/MAAE/AAME) in the present petition is a Diketene based Ester or aceto-acetate. Esters react with acids to liberate heat along with alcohols and acids. Strong oxidizing acids may cause a vigorous reaction that is sufficiently exothermic to ignite the reaction products. Heat is also generated by the interaction of esters with caustic solutions. Flammable hydrogen is generated by mixing esters with alkali metals and hydrides.

5. Methyl Acetoacetate finds uses in Pharmaceutical Industry, Agrochemical Industry, Polymer Industry, as a reactant in other industries. MAA is also used as a flavouring agent and in colourants.

6. Methyl Acetoacetate is classified in Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the subheading 29183040, as “Methyl Acetoacetate”. The product under consideration has dedicated customs classification under the Customs Tariff Act. On analyzing the import data, it has been observed that the subject goods are being imported under various other classifications as well. Therefore, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the proposed investigation.

Like Article

7. The petitioner has claimed that the subject goods, which are being allegedly dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Consumers can use and are using the two interchangeably. The Authority, for the purpose of the present investigation, has considered that the product produced by the domestic industry is comparable to the product imported from the subject countries in terms of essential product characteristics such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. The Authority treats the subject goods produced by the domestic industry as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

Subject Countries

8. The countries involved in the present investigation are United States of America (USA) and China PR.

Normal Value

9. The petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in accordance with para 7 of Annexure-I to the Rules.

10. The normal values have been constructed for the subject countries by adopting the rates of major raw materials prevailing in the domestic industry. For USA, utility prices prevailing in USA have been adopted. For China, utility prices of the domestic industry have been adopted. Other costs of the domestic industry have been considered for working out the constructed normal values.

Export Price

11. The petitioner has claimed export prices in respect of the subject countries on the basis of data obtained from the secondary source and the same have been adopted for initiation. The price adjustments on account of ocean freight, marine insurance, bank charges, commission, packing, Inland Freight, loading / unloading & port charges have been allowed to arrive at the net export price.

Dumping Margin

12. The petitioner has provided sufficient prima facie evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped into India to justify initiation of anti dumping investigation.

Injury and Causal Link

13. The petitioner has furnished prima facie evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price suppression and decline in profitability, return on capital employed etc. There is sufficient prima facie evidence of the injury being suffered by the petitioner caused by the dumped imports from the subject countries to justify initiation of an anti dumping investigation.

Period of Investigation

14. The period of investigation (POI) is the period from 01.04.2013 to 31.06.2014. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e., 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the proposed period of investigation will also be considered.

Submission of information

15. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street, New Delhi

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

17. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the communication. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

19. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

(a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

20. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

21. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

25. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

26. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

27. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, DESIGNATED AUTHORITY